



- : सराफा बाजार :-

गोल्ड 24 कैरेट = 1,55,500/10 ग्राम

22 कैरेट = 1,42,550/10 ग्राम

18 कैरेट = 1,16,660/10 ग्राम

चांदी = 2,50,000/किग्रा



संक्षिप्त समाचार

मानहानि विवाद में भाजपा प्रवक्ता ने दायर किया केस

नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कोकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर माफी और दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है।

‘पलाइंग डॉक्टर’

हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कुआलालंपुर। मलेशिया के बर्निगो द्वीप पर एयरपोर्ट के पास ‘पलाइंग डॉक्टर सर्विस’ का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत पांच लोग सवार थे। इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के एक मेडिकल अधिकारी, सहायक मेडिकल अधिकारी और दो नर्स शामिल थीं। हादसे के बाद खोज एवं बचाव अभियान जारी है। अभी किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

634 नेताओं से संवाद करेंगे भाजपा अध्यक्ष

देहरादून। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कुमाऊं दौरे के दौरान 634 नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ विकास योजनाओं, रोजगार, निवेश, पर्यटन, सड़क और कनेक्टिविटी पर फीडबैक लिया जाएगा।

नीली जर्सी में उतरेगी भारतीय हॉकी टीम

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में पुरानी नीली जर्सी में खेलेंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिकी ने बताया कि टीम किट के लिए नीला पहला और नारंगी दूसरा विकल्प चुना गया है।

अगस्त में ईवी बिक्री 53 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। फाड़ा के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में भारत में 2,98,448 इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 52.9 प्रतिशत अधिक है। कुल ऑटो खुदरा बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 12.3 प्रतिशत रही।

दिल्ली में यातायात रहेगा प्रभावित

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत मंगलवार रात 7:45 से 10 बजे तक मोटरकेड रिहर्सल होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस दौरान 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा।

तकनीकी देड़

एआई पर निवेश तो बढ़ा, पर निगरानी की तैयारी बहुत पीछे

- सिर्फ 22% कंपनियों के पास टैरिंटिंग-ऑडिट और जोरिवम आकलन की व्यवस्था
- भरोसेमंद एआई के लिए डेटा और गवर्नेंस मजबूत करने की चुनौती

एजेंसी, नई दिल्ली।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां अब एआई को केवल छोटे-मोटे काम आसान करने वाली तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि कारोबार के फैसलों और काम करने के तरीकों को बदलने वाले बड़े माध्यम के तौर पर देख रही हैं। यही वजह है कि देश में एंटरप्राइज एआई निवेश एक साल में 119 प्रतिशत बढ़ा है। यह वैश्विक औसत 110 प्रतिशत से भी अधिक है। अनुमान है कि 2027 तक भारत के औसत आईटी

बजट का 21.3 प्रतिशत हिस्सा एआई पर खर्च होने लगेगा। निवेश की इस तेज रफ्तार के साथ एक बड़ी चुनौती भी है। कंपनियां एआई को तेजी से अपना तो रही हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल पर निगरानी, जोरिवम आकलन और ऑडिट की बुनियादी व्यवस्था अभी उतनी मजबूत नहीं है। सर्विसनाउ की एंटरप्राइज एआई मैच्योरिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारत की केवल 22 प्रतिशत कंपनियों के पास एआई की टैरिंटिंग, ऑडिटिंग और जोरिवम आकलन की प्रक्रियाएं हैं।

भारत में करीब 54 प्रतिशत संगठन एआई एजेंट तैनात कर रहे हैं। ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जो इसानी निर्देश के आधार पर कई काम खुद करने में सक्षम होते हैं। हालांकि, केवल 11 प्रतिशत संगठन ऐसे हैं, जो एआई को पूरी तरह स्वायत्त वर्कफ्लो तक ले गए हैं। यानी कंपनियां एआई को काम सौंपने लगी हैं, लेकिन उसे पूरी तरह अपने फैसले

लेने की छूट देने में अभी सावधानी बरत रही है। इसकी वजह भी साफ है। करीब 60 प्रतिशत कंपनियां पारदर्शिता और गलत सूचना को लेकर चिंतित हैं। 55 प्रतिशत के लिए नियमन और अनुपालन बड़ी चुनौती है, जबकि 50

प्रतिशत कंपनियां डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। एआई की क्षमता का पूरा लाभ लेने के लिए केवल तकनीकी खरीदना पर्याप्त नहीं है। कंपनियों के अलग-अलग पुराने सिस्टम और उनमें बिखरा डेटा भी बड़ी समस्या है। अध्ययन के अनुसार, सिर्फ 18 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने पुराने अलग-अलग सिस्टम की जगह एकीकृत प्लेटफॉर्म अपनाया है। एआई-सक्षम वर्कफ्लो का भारत का स्कोर भी 100 में केवल 41 है।

यही कारण है कि 74 प्रतिशत कंपनियां डेटा की सटीकता, पहुंच और प्रबंधन को सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत वाला क्षेत्र मानती हैं। वहीं 56 प्रतिशत कंपनियां का कहना है कि पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से जोड़ना जरूरी है। जब डेटा और कामकाज की अलग-अलग प्रणालियां आपस में जुड़ी ही नहीं होंगी तो एआई की निगरानी, ऑडिट और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था बनाना मुश्किल होगा।

हे कि बाढ़ प्रभावित एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार एंटी लावा एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साफ-फाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा मच्छरों से बचाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद घरों एवं आसपास जमा पानी को साफ करें, पीने के पानी को सुरक्षित रखें तथा बुखार, उल्टी-दस्त अथवा अन्य संक्रामक रोगों के लक्षण दिखाएँ देते पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंजब न करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पंचायती राज एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर आवश्यक निरोधक कार्यवाई कार्य कर रही हैं, ताकि संक्रामक रोगों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।